नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

सीलिंग पर राहत की उम्मीद भोपाल का मास्टर प्लान जल्द

- एसीएस संजय दुबे दिल्ली पहुंचे, एसडी से चर्चा
- मंत्री विजयवर्गीय ने मसौदा तैयार होने के दिए संकेत

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 3 सितंबर. राजधानी भोपाल में 'सुप्रीम कोर्ट' के निर्देश के बाद सीलिंग की कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है और भोपाल बंद किया है, उससे अब सरकार भी बैकपुट पर है. इस बीच मामले को लेकर बीच का रास्ता निकालने की जुगत में लगी सरकार अब इस मामले में तेजी दिखाने लगी है.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और भोपाल नगर निगम की आयुक्त संस्कृति जैन गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचें है. यहां वे 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से परामर्श कर रहे हैं. जिससे कि कोई समाधान निकाला जा सके. राज्य सरकार अब सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलने की उम्मीद में है.

इस बीच प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी गुरुवार को सीलिंग और भोपाल मास्टर प्लान को लेकर बड़ा बयान दिया. भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने स्वीकार किया कि सीलिंग की कार्रवाई से पूरे भोपाल के व्यापारी काफा परेशान हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग के कई बड़े अधिकारी नई दिल्ली गए हैं. इस मामले में वे 'सुप्रीम कोर्ट' के बड़े वकीलों से परामर्श करेंगे और कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे, जिससे कि भोपाल के लोगों को कोई नुकसान नहीं हो. विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर चर्चा चल रही है. इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा. मौजूदा मास्टर प्लान 1995 में लागू की गई थी, जिसकी अवधि दिसंबर 2005 में ही समाप्त हो गई है, तब से लेकर अब तक भोपाल चारों ही क्षेत्रों में बेतरतीब तरीके से बढ़ रहा है. किस क्षेत्र में आवासीय और कौन क्षेत्र व्यवसायिक होगा, ये तय नहीं होने से कहीं भी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं. इसलिए अब जो संकेत हैं, उसके मुताबिक राज्य सरकार 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले भोपाल का मास्टर प्लान लागू करने को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है. संभव है कि जन्माष्टमी के दिन भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजधानीवासियों को ये बड़ी सौगता देने की घोषणा कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. इसे अब मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है.

हलफनामा दे सकती है सरकार

मिले संकेतों के मुताबिक 15 सितंबर को राज्य सरकार 'सुप्रीम कोर्ट' में सीलिंग के मामले में हलफनामा दे सकती है. इसमें अब तक की गई कार्यवाही का पूरा ब्यौरा तो दिया ही जाएगा, साथ ही मानवीय पहलु के बारे में अवगत कराया जाएगा. यह भी बताया जाएगा कि यदि निर्णय पर पूरी तरह अमल किया गया तो राजधानी भोपाल में ही लाखों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. वहीं रहवासियों की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा.

सीएम कर सकते हैं घोषणा

भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर भी राज्य सरकार अब तेजी से काम कर रही है. इसे लेकर उच्च स्तर पर सरकार की नाकामी पहले ही उजागर हो चुकी है, वहीं जनप्रतिनिधि भी मास्टर प्लान लागू करने के लिए दबाव नहीं बना सके हैं, इसलिए भी उनके पास मुंह छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का खामियाजा राजधानी के लोगों को इसलिए भुगतना पड़ रहा है क्योंकि पिछले दो दशक से भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आ सका है.

2020 में बना था मास्टर प्लान

दिसंबर 2005 में भोपाल मास्टर प्लान की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ष 2010 में पांच वर्ष बाद सरकार ने सुध ली थी और मास्टर प्लान-2021 तैयार किया गया था, तब से लेकर अब तक मास्टर प्लान का प्रारूप कागजों में ही तैयार होता रहा, कभी विवाद तो कभी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते ये प्लान परवान नहीं चढ़ सका. बाद में वर्ष 2031 के हिसाब से और अब वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है.

दो साल के बच्चे ने भी तोड़ा दम, बालाघाट रहा बंद

27 बच्चों की मौत पर भड़के लोग

नवभारत न्यूज

बालाघाट, 3 सितंबर. जिले में 27 आदिवासी बच्चों की मौत के बाद आदिवासी समुदाय में भारी आक्रोश है.

खसरे और मलेरिया से हुई इन मौतों के विरोध में आदिवासी समुदाय ने बालाघाट में बंद का आह्वान किया. इसी बीच बोंदारी निवासी बिसन धुर्वे के दो साल के बेटे की भी मौत हो गई. परिजन के मुताबिक बीमार होने के बाद आकाश को जिला अस्पताल लाया गया था. बंद का असर पूरे जिले में साफ दिखा . लोगों ने स्वेच्छा से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे.

मेट्रो का निकला मुहूर्त, कल लोकार्पण

केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिखाएंगे हरी झंडी

नवभारत न्यूज

इंदौर, 3 सितंबर. आखिरकार मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लोकार्पण का कार्यक्रम तय हो गया. कल शनिवार 5 सितंबर को शाम मेट्रो रेल के 11 किलोमीटर लंबे दूसरे चरण का लोकार्पण होगा.

मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, शहरी विकास राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री आ रहे है. मेट्रो रेल के शुभारंभ पर प्रदेश के दोनों कबीना मंत्री भी मौजूद रहेंगे. शहर में अब मेट्रो रेल पूरे 17 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने लगेगी. मेट्रो गांधी नगर से मालवीय नगर चौराहे तक चलेगी. कल शाम 4 बजे मेट्रो रेल

नवभारत खबर का असर

7500 करोड़ खर्च, मेट्रो खड़ी

इंदौर में राजनीतिक खींचतान के चलते आम जनता सुविधा से वंचित

के दूसरे चरण का शुभारंभ समारोह तय हो गया है. कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहरलाल खट्टर, शहरी विकास राज्यमंत्री तोखन साहू, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे. ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा इंदौर में 2018 में प्रस्ताव किया गया था. इसके बाद मई 2023 में ट्रायल रन किया गया और फरवरी 24 में मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो गया था. तब सिर्फ 6 किलोमीटर रन शुरू किया गया था. जिसमें गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर 5 स्टेशन तक मेट्रो चलाई जा रही थी.

मेट्रो में यात्रा भी करेंगे

मेट्रो के दूसरे चरण के 11 किलोमीटर लंबे रन का शुभारंभ समारोह ब्रिलिएंट कन्वेशन सेंटर या माथुर सभागृह में आयोजित होगा. शुभारंभ के बाद केंद्रीय मंत्री खट्टर, राज्यमंत्री साहू, मुख्यमंत्री यादव , मंत्री विजयवर्गीय, मंत्री सिलावट एवं विधायक मेट्रो में बापट चौराहे से मालवीय नगर तक अधिकारियों एवं नागरिकों के साथ यात्रा भी करेंगे.

लोक निर्माण के इंजीनियर ने भ्रष्टाचार से कर डाला 20 करोड़ का 'निर्माण'

ईओडब्ल्यू ने छिंदवाड़ा, बालाघाट और भोपाल में एक साथ मारी रेड

नवभारत न्यूज

भोपाल, 3 सितंबर. लोक निर्माण विभाग बालाघाट का कार्यपालन यंत्री कमल किशोर सिंगारे करोड़पति निकला. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर की तीन टीमों ने गुरुवार तड़के कार्यपालन यंत्री के छिंदवाड़ा, बालाघाट और भोपाल के ग्रीन मीडोज स्थित स्थित आवास एवं अन्य परिसरों पर एक साथ छापेमारी की.

अब तक की जांच में करीब 11 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं. इसमें कोठीनुमा मकान, जमीन, शापिंग कॉम्प्लेक्स, वाहन, आभूषण, नगदी, बैंक खातों और अन्य संपत्ती मिली है. एजेंसी ने प्रॉपर्टी का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए आंकी है. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.

छिंदवाड़ा स्थित आवास से अब तक सामने आई संपत्तियों में करीब 3 करोड़ रुपए का आलीशान मकान और जमीन, 7.50 लाख रुपए नकद, करीब 1 करोड़ रुपए का घरेलू सामान, 350 ग्राम सोने के आभूषण जिनकी अनुमानित कीमत 52 लाख रुपए है, चांदी के आभूषण करीब 1.20 लाख रुपए, एक्सयूवी-700 करीब 22 लाख रुपए, नई स्कॉर्पियो करीब 27 लाख रुपए, ट्रैक्टर और तीन मोटरसाइकिल करीब 4 लाख रुपए की शामिल हैं. इसके अलावा करीब 1.50 करोड़ रुपए का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी सामने आया है. आरोपी और उसके परिजनों के नाम से विभिन्न बैंकों में 12 खाते, लॉकर के दस्तावेज मिले हैं.

पूर्व विधायक पर ईडी का शिकंजा

- तेंदूखेड़ा से जप्त किए 25 लाख रुपए
- कार्रवाई को बता रहे राजनीति से परिपूर्ण

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 3 सितंबर. कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शर्मा पर ईडी के शिकंजा कसने की तैयारी दूसरे दिन भी जोरों पर रही. कार्यवाही के दूसरे दिन ईडी की टीम ने तेंदूखेड़ा स्थित वार्ड क्रमांक 09 वंशिका कंस्ट्रक्शन से जुडे एक जवाबदार को खंगाला और वहां शराब कारोबार के रखे हुए 25 लाख रुपए जप्त किए.

खबर है कि टीम ने कई अहम दस्तावेज भी जप्त किए हैं जिससे घोटालों की तह तक पहुंचा जा सके. उधर वंशिका कंस्ट्रक्शन के रामलाल झारिया तेंदूखेड़ा ने दो टूक कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक दवाब के चलते हुई है. टोलों को लेकर ईडी को शिकायत की गई थी लेकिन जांच के दौरान टीम को किसी भी टोल में अनियमितता नहीं मिली है और न ही किसी सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी मिली है. लेकिन टीम ने कार्यालय में शराब कारोबार के रखे 25 लाख रुपए जप्त किए और फिर टीम रकम लेकर रवाना हो गई है. रामलाल के अनुसार नरसिंहपुर मे राजमार्ग के वंशिका ऑफिस और उनके तेंदूखेड़ा स्थित आवास पर गत दिवस सुबह करीब 7 बजे से देर रात करीब 3 बजे तक ईडी की कार्यवाही चली.